

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

30.06.2016 की स्थिति के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (3) के अधीन मानीटरिंग और रिपोर्ट

October, 2016 माह के दौरान प्राप्त कुल आवेदन : 83 और प्राप्त राशि: रु. 60/-

भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वयन करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को दर्शाते हैं													
(छ) सुधार के लिए समुचित सुझाव जो विकल्प, सुधार, आधुनिकीकरण एवं सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के लिए इस अधिनियम अथवा अन्यम् विवरण अथवा सामान्य विवरण अथवा अन्यम् किसी संगत मामले में संशोधन के लिए सुधार के लिए अपेक्षित हो													

** विभाग की वेबसाइट <http://darpg-grievance.nic.in> में भारत में कहीं भी, किसी भी वेब आधारित सुविवरण के जरिए कोई भी नागरिक शिकायतें दर्ज करा सकता है।